संसद के समक्ष अभिभाषण – 10 फरवरी 1964*

लोक सभा	-	तीसरी लोक सभा
सत्र	-	वर्ष का पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	डॉ. एस. राधाकृष्णन
भारत के उपराष्ट्रपति	-	डॉ. जाकिर हुसैन
भारत के प्रधानमंत्री	-	पंडित जवाहरलाल नेहरू
लोक सभा अध्यक्ष	-	सरदार हुकम सिंह

माननीय सदस्यगण,

संसद के नए इजलास का कार्यभार उठाने के लिए एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूं।

हाल ही में जो साल खत्म हुआ है उसमें भारत की सरकार और जनता को कुछ ऐसे मसलों का सामना करना पड़ा जो बड़े और पेचीदा थे। मगर तरह-तरह की कठिनाइयों और रुकावटों के बावजूद हम अपने लक्ष्य की तरफ बराबर बढ़ते रहे हैं, जो यह रहा है कि अपने देश में हम लोकतंत्रीय तरीकों से समाजवादी समाज की स्थापना करें और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में शांति और सहयोग बनाए रखें।

हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना ने तीन वर्षों में जो प्रगति की उसका मूल्यांकन करने पर योजना कमीशन को पता चला है कि बाकी के दो वर्षों में बहुत बड़ी मंजिल तय करनी है, और अगर हम चाहते हैं कि हमारी उम्मीदें पूर्ण हों तो हमको जी-जान से कोशिश करनी पड़ेगी।

दोबारा मूल्यांकन करने पर यह जरूरी था कि हम उन क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान देते जिनमें लगता है कि हम अपने लक्ष्य से पीछे रह गए हैं लेकिन इसके मारे वह कमी नहीं है कि जो प्रगति हमने की है या जो सफलता हमें मिली है उसे हम कम करके

---

* भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे उपराष्ट्रपति डॉ. जाकिर हुसैन द्वारा दिया गया अभिभाषण।

देखें या उसकी तरफ से आंखें फेर लें। औद्योगिक उत्पादन बराबर बढ़ता रहा है ऐसी आशा की जाती है कि पिछले साल जितना औद्योगिक उत्पादन हुआ था, 1963-64 में उससे 7-8 प्रतिशत अधिक होगा। कोयला और इस्पात जैसे बुनियादी उद्योगों में और प्रगति हुई है। इस्पात के कारखाने लगभग पूरी ताकत से उत्पादन कर रहे हैं। देश के कुछ भागों में बिजली की कमी महसूस की गई है लेकिन कुल मिलाकर ज्यादा बिजली पैदा की गई है और परिवहन की कठिनाइयां भी कम हुई हैं। निर्यात से हमारी आमदनी बढ़ी है और हमारे मित्र देश हमें जो बाहरी सहायता देते हैं उससे हमारे विदेशी मुद्राकोष की हालत सुधरी है और देश को जो अदायगियां करनी हैं उनके कारण पिछले साल उस पर जितना दबाव पड़ रहा था इस साल नहीं पड़ रहा है।

पब्लिक सेक्टर के प्रतिष्ठानों ने अच्छी-खासी तरक्की की है। 16 नवम्बर, 1963 को चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने भारत में बना पहला ए.सी. बिजली का इंजन चालू किया। भोपाल के हैवी इलेक्ट्रिकल प्लांट का उत्पादन बढ़ गया है। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन ने किरीबुरु की लोहे की खानों का विकास करीब-करीब पूरा कर लिया है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन ने गुजरात में तेल और गैस के काफी बड़े जखीरों का पता लगा लिया है ट्रांबे के एटॉमिक एनर्जी इस्टेबलिशमेंट ने रेडियो आइसोटोप्स का निर्यात करना शुरू कर दिया है।

कई ऐसे नए प्रोजेक्ट हैं जिनको अमल में लाने की दर्जे-ब-दर्जे तैयारियां हो रही हैं और इनसे आने वाले वर्षों में हमारी आर्थिक व्यवस्था को नई शक्ति मिलेगी। पब्लिक सेक्टर के तीन इस्पात के कारखानों को और बड़ा करने की योजना चल रही है। दुर्गापुर के अलॉय एंड टूल स्टील प्लांट में काम हो रहा है। बोकारो में इस्पात का कारखाना खोलने के काम की शुरुआत कर दी गई है। तारापुर और राणा प्रताप सागर, राजस्थान में एटमी शक्ति के स्टेशनों को स्थापित करने के लिए क्रमशः संयुक्त राज्य अमरीका और कनाडा से करार किए जा चुके हैं। जब कुछ और ऐसे कारखाने बनकर तैयार हो जाएंगे, जिनके लिए जरूरी विदेशी सहायता ली जा चुकी है, तब हम अपनी तीसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य से बहुत पीछे न रहेंगे। साथ ही हमारी चौथी योजना के शुरू के वर्षों में हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ और बिजली के कारखाने खोलने के संबंध में पहले से कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

ये बातें संतोषजनक हैं, फिर भी हमारा आर्थिक विकास उस गति से नहीं हो रहा है जो हमारी योजना का लक्ष्य था। इसकी खास वजह है खेती की पैदावार का घटना, जो 1962-63 में 3.3 प्रतिशत कम हुई है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान खेती को यके-बाद-दीगरे खराब मौसम का सामना करना पड़ा है। हमारे सामने आज सबसे जरूरी काम यह है कि खेती की पैदावार को बराबर बढ़ाया जाए।

तीसरी योजना के पहले दो सालों में खेती के काम को बढ़ाने के लिए बराबर कोशिश की गई है। लगभग 60 लाख एकड़ नई जमीन को सिंचाई की सुविधा पहुंचाई गई है। कोशिश हो रही है कि चालू वर्ष में इसके अलावा 5.5 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन को सिंचाई की सुविधा दी जाए। छोटे पैमाने पर सिंचाई, भूमि-संरक्षण और खेती की पैदावार को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को 19.15 करोड़ रुपये और दिए गए।

गल्ले की पैदावार में जो कमी आई है उसका कीमतों के स्तर पर बुरा असर पड़ा है। सरकारी गोदामों से ज्यादा गल्ला निकाल कर, जहां मुमकिन हो, सस्ते अनाज की और ज्यादा दुकानें खोलकर, गल्ले को ठीक जगहों पर पहुंचाकर, और उधार देने की नीति बरतकर, हर तरह कोशिश की गई है कि गल्ले का दाम चढ़ने न पाये। अप्रैल, 1963 से फैक्टरी से निकलने पर चीनी के दाम तथा उसके वितरण पर फिर से कंट्रोल लगा दिया गया है।

जो बात खेती की पैदावार के लिए कही जा सकती है, वही औद्योगिक उत्पादन के लिए भी ठीक है कि आखिर में चलकर दामों में ठहराव तभी आएगा जब पैदावार इतनी बढ़ जाये कि उससे बढ़ती हुई मांग पूरी की जा सके। खेती के क्षेत्र को मजबूत बनाने और खेती की पैदावार को बढ़ाने के लिए जो उपाय हमने किए हैं उनका जिक्र मैं कर चुका हूं। इन तथा और दूसरे उपायों से, साथ ही खेती की खास-खास फसलों का भाव ठीक रखने की नीति से, ऐसा समझा जाता है कि खेती की पैदावार भी बढ़ेगी और उत्पादन की क्षमता भी।

औद्योगिक विकास की रफ्तार तेज करने के लिए कई तरह के प्रशासन सम्बन्धी परिवर्तन किए गए हैं, काम करने के तरीकों को आसान किया जा रहा है, और कुछ कंट्रोलों में ढील दे दी गई है। खेती और उद्योग दोनों के लिए, खासकर सरकारी क्षेत्र और छोटे पैमाने पर उद्योगों के लिए आर्थिक सहायता बढ़ाई जा रही है।

प्रशासन के काम में चुस्ती लाने के लिए और भ्रष्टाचार और बेइमानी के खिलाफ की गई शिकायतों पर फौरन और कारगर ढंग से ध्यान देने के लिए यह तय किया गया है कि एक सेण्ट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना की जाए जिसका दर्जा, अपने क्षेत्र में, लगभग वैसा ही होगा जैसा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का। इसकी सालाना रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों के सामने रखी जाया करेगी।

जुलाई, 1963 में हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और पांडिचेरी की यूनियन टेरीटरी में विधान सभाएं और मंत्रिपरिषदें बनाई गईं, और पिछली दिसम्बर में गोवा, दमन, दीव में भी इस तरह की सभा और परिषद् की स्थापना हुई। 1 दिसम्बर, 1963 को नागालैंड राज्य बनाया गया और जनवरी, 1964 में उसकी विधान सभा के लिए चुनाव किए गए।

हालांकि हमारी सीमा पर लड़ाई नहीं हुई, फिर भी सारे साल चीन से खतरा बना रहा। कोलम्बो प्रस्तावों के बारे में चीन अभी तक अपना जिद्दी रवैया अपनाए हुए है और उसने हमारी सीमाओं पर अपनी फौजी शक्ति बढ़ाई है।

हम शांति के कायल हैं और इस नीति के भी कि संसार के तमाम झगड़ों को शांतिपूर्ण तरीकों से हल किया जाए, फिर भी हम अपने बचाव की तरफ से ग़ाफ़िल नहीं हो सकते। इस वर्ष के दौरान हमारी फौज और हवाई सेना को सुधारने और बढ़ाने के लिए बहुत से कदम उठाए गए। हमारी हथियारबंद फौजों की सभी शाखाओं में रंगरूटों की भर्ती संतोषजनक रही है लेकिन तकनीकी सेवाओं में काम करने वाले योग्य आदमियों की कमी महसूस की जा रही है। सेना में काम करने वाले लोगों की नौकरियों की शर्तों में बहुत से सुधार किए गए हैं। जो कुछ बड़े-बड़े उपाय किए गए हैं, वे ये हैं: कमीशन-प्राप्त अफसरों की पेंशन दरों में संशोधन; अफसर दर्जे से निचले दर्जे के जो कर्मचारी मर गये हों, उनकी विधवाओं और उन पर निर्भर लोगों को पेंशन का लाभ पहुंचाने में उदारता; और छोटी रकम की पेंशन में बढ़ोतरी।

हमारी सेनाओं को साज-सामान से लैस करने की दिशा में हमें संयुक्त राज्य अमरीका, युनाइटेड किंगडम और राष्ट्रमंडल के कई देशों से काफी मदद मिल चुकी है और आगे और भी साज-सामान आने को हैं। सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ की सरकार ने हमें कई सामान ढोने वाले हवाई जहाज और अन्य उपकरण दिये हैं और वे हमारे देश में आवाज की गति से तेज चलने वाले हवाई जहाज तैयार करने का कारखाना बनाने में हमारी मदद कर रहे हैं। इन देशों ने हमें जो सहायता दी है, उसके लिए हम उनके आभारी हैं।

हमारी रक्षा सेनाएं साज-सामान से पूरी तरह लैस रहें, इसके लिए हम चाहते हैं कि उसका ज्यादा-से-ज्यादा उत्पादन हमारे ही देश में हो। हमारी रक्षा के लिए विदेशों से जिस सहायता की व्यवस्था है, उसके अंतर्गत जरूरी प्लांट और मशीनें मंगाकर हम सामरिक उद्योगों में उत्पादन का आधार मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं 1963-64 में आर्डनेंस फैक्टरियों में 100 करोड़ रुपये से अधिक का उत्पादन होने की आशा है, जबकि 1962-63 में यह उत्पादन 63 करोड़ रुपये का था और 1961-62 में 41.45 करोड़ रुपये का।

अपनी घोषित नीति के अनुसार, हम दुनिया के तमाम देशों के साथ मित्रता और सहयोग का सम्बन्ध रखने की कोशिश करते रहे हैं। साथ ही हमने शांतिपूर्ण सह-जीवन और गुटों से अलग रहने की नीति का भी पालन किया है। हमारी इस नीति का समर्थन और उसकी सराहना कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों तथा पश्चिम एशिया और उत्तर अफ्रीका के देशों ने की है।

हमारे राष्ट्रपति को संयुक्त राज्य अमरीका, यूनाइटेड किंगडम, नेपाल, अफगानिस्तान और ईरान जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और उनकी सरकार तथा वहां के लोगों का प्रेम-पूर्ण स्वागत-सत्कार पाकर हमें बड़ी खुशी हुई है। सद्भाव और मित्रता को और बढ़ावा देने की गरज से मैंने इथोपिया, सूडान और संयुक्त अरब गणराज्य की यात्रा की। इसके अलावा, हमारे कई मंत्रियों और अन्य सम्मानित व्यक्तियों ने इसी भावना से संसार के कई देशों का दौरा किया।

इस वर्ष के दौरान हमारी सरकार को जिन सम्मानित अतिथियों के भारत आने पर उनका स्वागत-सत्कार करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वे ये हैं: महामहिम लाओस नरेश, महामहिम नेपाल नरेश और उनकी महारानी, जोर्डन के महामहिम शाह, साइप्रस गणराज्य के उप-राष्ट्रपति, संयुक्त अरब गणराज्य की कार्यकारिणी परिषद् के प्रधान, सोमाली गणराज्य के प्रधान मंत्री, नाइजीरिया संघीय गणराज्य के उत्तरी क्षेत्र के मुख्य मंत्री, न्यू साउथ वेल्स के मुख्य मंत्री, संयुक्त राज्य अमरीका के विदेश मंत्री, अर्ल माउंटबेटन ऑफ बर्मा, डेनमार्क की राजकुलमान्या राजकुमारी मार्गरेट और सोवियत अंतरिक्ष यात्री वेलेन्तीना तेरेशकोवा निकोलायवा और उनके दो साथी।

प्रेसीडेन्ट केनेडी की हत्या का समाचार सुनकर हमें सदमा पहुंचा और दु:ख हुआ। उनकी मृत्यु से भारत ने एक सच्चा मित्र खोया और दुनिया ने अमन और दोस्ती का जबर्दस्त हिमायती। हम प्रेसीडेन्ट जॉनसन के उस एलान का स्वागत करते हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि वे तनाव कम करने और दुनिया में अमन बनाए रखने के अहम और मुश्किल काम में स्वर्गीय प्रेसीडेन्ट केनेडी की नीति का ही पालन करेंगे; साथ ही वे उन देशों के आर्थिक विकास में सहयोग भी देंगे जो कम विकसित हैं।

अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जो अति उत्साहवर्धक घटनाएं हुई हैं उनमें से एक यह है कि संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत संघ ने बाहरी अंतरिक्ष में एटमी हथियारों पर रोक लगाने के सिद्धांत को मंजूर कर लिया है। इसे बाद में संयुक्त राष्ट्रसंघ ने भी स्वीकार कर लिया है। यह घटना और परीक्षण रोकने का करार नि:शस्त्रीकरण करने और सच्ची शांति स्थापित करने की दिशा में पहले अहम कदम हैं, जिन्हें उसी वातावरण में हासिल किया जा सकता है जिसमें एक-दूसरे पर भरोसा किया जा सके और एक-दूसरे के साथ मिल-जुल कर रहा जा सके। चेयरमैन खुश्चेब ने प्रदेश या सीमा के झगड़ों को तय करने में शक्ति का प्रयोग न करने के बारे में एक अंतर्राष्ट्रीय करार करने का जो प्रस्ताव किया है, उसमें निहित सिद्धांत से हम मोटे तौर पर सहमत हैं, और आशा करते हैं कि जिन प्रमुख राष्ट्रों का इनसे सरोकार हो, वे परस्पर विश्वास की भावना के इस अहम सुझाव पर एक ऐसा समझौता कर सकेंगे जो सबके लिए संतोषजनक हो और सबको मंजूर हो।

नेपाल के साथ हमारे सम्बन्ध बहुत ही मजबूत और मित्रतापूर्ण हैं और दोनों देश एक-दूसरे की समस्याओं और आकांक्षाओं को पूरी तरह समझते हैं और उनके साथ पूरी हमदर्दी रखते हैं। हम भूटान के आर्थिक और सामाजिक विकास में बराबर मदद दे रहे हैं।

महाराजा सिक्किम की मृत्यु से भारत और सिक्किम, दोनों को जो जबर्दस्त सदमा पहुंचा है वह संसद के सदस्यों से छिपा नहीं है। उनके सुपुत्र, राज्यमान्य पाल्देन थोंडुप नामग्याल दिसम्बर, 1963 में गद्दी पर बैठे।

हमें इस बात की खुशी है कि कुवैत को संयुक्त राष्ट्र में वह स्थान मिल गया है जिसका वह हकदार है। कीनिया और उगांडा की आजादी पर हमें खुशी है और इस पर भी कि अफ्रीका के दूसरे देश जल्द आजाद होने को हैं। हम चाहते हैं कि इन देशों के साथ हमारे संबंध ज्यादा से ज्यादा नजदीकी हों और हम विकास के उन बहुत से कार्यभारों में भी उनका हाथ बंटा सकें जो नए आजाद मुल्कों को उठाने पड़ते हैं।

हमें उन अफ्रीका निवासियों के साथ पूरी हमदर्दी है और हम उनकी पूरी-पूरी हिमायत करते हैं जो अब भी पुर्तगाल की उपनिवेशी हुकूमत में हैं और आजादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। अफ्रीका और दुनिया के दूसरे मुल्कों के उन लोगों के साथ भी हमारी हमदर्दी है और हम उनकी हिमायत करते हैं जो दक्षिण अफ्रीकी सरकार की रंग और जातिभेद की नीतियों को खत्म कराने की कोशिशें में लगे हैं।

जहां तक पाकिस्तान के साथ हमारा सम्बन्ध है, मुझे यह कहते हुए बड़ा अफसोस होता है कि पाकिस्तान की मंशा समझौता करने की कतई नहीं है। "कश्मीर और उससे जुड़े हुए दूसरे मसलों" पर दिसम्बर, 1962 में मंत्रियों के स्तर पर बातचीत का जो सिलसिला शुरू हुआ था वह पांच दौरों के बाद 16 मई, 1963 को कटु वातावरण में टूट गया। सच तो यह है कि इस बातचीत के सफल होने की आशा तो तभी टूट गई थी जब पाकिस्तान ने चीन के साथ सीमा समझौता करके कश्मीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा चीन को दे दिया था जिस पर पाकिस्तान ने फौजी कब्जा कर रखा था। इसके बावजूद और भारत के खिलाफ चीन के साथ सांठगांठ करने की दूसरी कारस्तानियों के बावजूद भी, हमारी सरकार धीरज के साथ बातचीत करती रही लेकिन इस बातचीत के पांचों दौरों ने यह बात साफ कर दी कि पाकिस्तान तर्क और तथ्य के आधार पर समझौता करना नहीं चाहता और इसके पीछे उसका मकसद सिर्फ यह है कि उसे भारत के खिलाफ प्रोपेगंडा करने का मौका मिल सके।

इन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के बावजूद, भारत-पाकिस्तान की समस्याओं को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने का रास्ता भारत खोजता रहा, और जहां तक हो सका, उसने पाकिस्तान द्वारा चलाए 'भारत से नफरत' के आंदोलन को भी नजर अंदाज किया। हमारे प्रधान मंत्री ने एक बार फिर यह अपील की कि भारत और पाकिस्तान के बीच

'जंग न करने का एलान' किया जाए और साथ ही भारत और पाकिस्तान के सभी झगड़ों को शांतिपूर्ण तरीकों से हल करने की कोशिश की जाए। लेकिन प्रधान मंत्री की अपील पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और साल के खत्म होते-होते भारत और पाकिस्तान के संबंध उससे भी कहीं ज्यादा खराब हो गए जितने कि वह 1962 में थे।

दिसम्बर, 1963 के आखिरी हफ्ते में कश्मीर के कुछ समाजविरोधी लोगों ने हजरतबल की दरगाह से पवित्र बाल चुराकर जो घोर अपराध किया उससे कश्मीर और बाकी भारत के लोगों को बहुत चिन्ता हुई। लेकिन कश्मीर के अधिकारियों को सहायता करने में हमारी सरकार ने बड़ी फुर्ती से कार्रवाई की जिसके कारण पवित्र बाल मिल गया और इससे समूचे भारत के लोगों को बड़ी खुशी हुई और राहत मिली। परन्तु पाकिस्तान के अधिकारियों ने इस दुर्घटना का फायदा उठाकर पाकिस्तान में भारत-विरोधी और फिरकापरस्ती की भावना फैलाई जिसका नतीजा यह हुआ कि पूर्वी पाकिस्तान* में कई जगहों में, जिसमें कि ढाका भी शामिल था, जोर के दंगे हुए, कानून और इन्तजाम खत्म हो गया और उसकी वजह से पूर्वी पाकिस्तान* में अल्पसंख्यक जाति के कई सौ आदमी मार डाले गए और उनकी सम्पत्ति को भी बहुत नुकसान पहुंचाया गया। कलकत्ता** और पश्चिमी बंगाल के कुछ दूसरे इलाकों पर इन दुर्घटनाओं का बुरा असर पड़ा, लेकिन सरकार ने बलवाइयों के खिलाफ बड़ी तेजी और सख्ती से कार्रवाई की और, जाति-धर्म का ख्याल किए बिना, भारत के सभी नागरिकों के जानमाल की पूरी हिफाजत की। हमारे राष्ट्रपति ने यह प्रस्ताव भी रखा कि भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रपति मिलकर दोनों देशों में रहने वाली विभिन्न जातियों से मेल-मिलाप और शांति से रहने की अपील करें और इस अपील पर कार्रवाई करने के कुछ अमली तरीके भी सुझाए लेकिन पाकिस्तान ने अब तक इन सुझावों को मानने से इन्कार ही किया है। पूर्वी पाकिस्तान* में जो दंगे हुए उनमें वहां के विभिन्न इलाकों में रहने वाली अल्पसंख्यक जाति के लोगों की जान और माल का भारी नुकसान हुआ। नतीजा यह हुआ कि आज हमारे सामने पूर्वी पाकिस्तान* से बहुत बड़ी तादाद में अल्पसंख्यक जाति के लोगों के भारत आने की समस्या खड़ी हो गई है।

संसद के सदस्यगण! मैंने आप लोगों के सामने पिछले वर्ष देश की खास-खास कामयाबियों और मसलों का एक ब्यौरा रखा है। हमें जो काम करने हैं और हमारे ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं, उनका एक छोटा-सा खाका मैंने आपके सामने पेश किया है। इन पर आप अच्छी तरह गौर करें, इन्हें समझें और इन्हें पूरा करने और निभाने में अपना ज्यादा से ज्यादा सहयोग दें। हमारी सरकार हर तरह से अपने देश और देश के निवासियों की आजादी और इज्जत को बनाये रखने की, देश में एकता और खुशहाली बढ़ाने की, और एक ऐसा लोकतंत्रीय और समाजवादी समाज बनाने की कोशिश करती रहेगी जिसमें शांतिपूर्ण तरीकों और सबकी रजामंदी से प्रगति की जा सके।

---

*अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है।

**अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है।

1963 के दौरान संसद ने 58 बिल पास किए थे। 19 पिछले बिल अभी बाकी हैं जिन पर आपको विचार करना है। विचार के लिए जो बिल आपके सामने रखे जाएंगे उनमें ये भी शामिल होंगे:–

(1) कंपनी (संशोधन) बिल।

(2) भारतीय फसल बीमा बिल।

(3) भार एवं माप-मानक (संशोधन) बिल।

(4) भारतीय रेलवे (दूसरा संशोधन) बिल।

(5) केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली पर लागू बम्बई सहकारी समिति अधिनियम, 1925 को खत्म करने और कुछ संशोधनों के साथ पंजाब सहकारी समिति अधिनियम, 1961 दिल्ली में लागू करने से संबद्ध बिल।

(6) विदेशी मुद्रा नियमन (संशोधन) बिल।

(7) संविधान (अट्ठारहवां संशोधन) बिल।

(8) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) बिल।

(9) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) बिल।

भारत सरकार के 1964-65 के माली साल की आमदनी और खर्च के अंदाजे का ब्यौरा आपके सामने रखा जाएगा।

संसद सदस्यगण! मेरी कामना है कि आपको अपने कार्य में सफलता मिले। मुझे पूरा विश्वास है कि विवेक, सहनशीलता और सहयोग की भावना से आप लोग काम करते रहेंगे। मेरी शुभकामना है कि आपके प्रयत्नों से हमारे देशवासियों को अधिकाधिक सुख और संतोष प्राप्त हो, हमारी मातृभूमि सुस्थिर और सुरक्षित रहे और संसार में शांति और सहयोग की भावना समुन्नत हो।